1. मॉड्यूल और इसकी संरचना का विवरण

मॉड्यूल विवरण	
विषय नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	भारतीय आर्थिक विकास 01 (कक्षा XI, सेमेस्टर - 1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	ग्रामीण विकास - भाग 1
मॉड्यूल Id	keec_10601
पूर्वअपेक्षित ज्ञान	मूल अर्थशास्त्र के बारे में आवश्यक जानकारी
उद्देश्य	इस पाठ के माध्यम से जाने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे : 1. ग्रामीण विकास में प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां 2. ग्रामीण विकास का महत्व भारत 3. ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण, ग्रामीण ऋण और इसके स्रोत 4. सहकारी क्षेत्र के कार्य और कमजोरियाँ 5. RRBs और नाबार्ड के कार्य 6. भारत में कृषि ऋण की समस्या को सुधारने के सुझाव
मुख्य शब्द	ग्रामीण विकास, ग्रामीण ऋण, ग्रामीण ऋण, सहकारी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2. Development Team

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Mohd. Mamur Ali	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Mr. Amit Mehrotra	Arwachin International School, Delhi
Review Team	Dr. Meera Malhan Dr M U Farooque	DCAC. University of Delhi Satyawati College (Evening), University of Delhi
Translator	Mr. Pushpendra Kumar Rana	PGT Economics, Birla Balika Vidyapeeth Pilani

विषय - सूची :

1. परिचय
2. ग्रामीण विकास का महत्व
3. ग्रामीण ऋणग्रस्तता और इसके कारण
4. ग्रामीण ऋण, ग्रामीण ऋण के प्रकार और इसके स्रोत
5. संस्थागत स्रोत या औपचारिक क्षेत्र
6. सहकारी क्षेत्र की कमजोरियाँ
7. वाणिज्यिक बैंक
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
9. एसएचजी और माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम
10. भारत में कृषि ऋण की समस्या को सुधारने के सुझाव
11. सारांश

परिचय

ग्रामीण विकास एक ऐसा शब्द है जो अनिवार्य रूप से उन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्रवाई पर केंद्रित है जो मुख्यतः कृषि प्रधान हैं। ग्रामीण विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई पहल की आवश्यकता है, वे हैं:

i. संसाधनों का विकास जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ ।
ii. भूमि सुधारों का कार्यान्वयन।
iii. साक्षरता के स्तर में सुधार, विशेष रूप से, महिला साक्षरता, वयस्क साक्षरता और कौशल विकास।
iv. प्रत्येक इलाके में उत्पादक संसाधनों का विकास।
v. गरीबी को कम करने और आबादी के कमजोर वर्गों की जीवन स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए विशेष उपाय।

vi. बुनियादी ढांचा विकास जैसे बिजली, सिंचाई, ऋण, विपणन, परिवहन की सुविधा, जिसमें गाँव की सड़कों का निर्माण और आसपास के राजमार्गों के लिए *फीडर* रोड, कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए सुविधाएं और सूचना प्रसार शामिल हैं।

ग्रामीण विकास का महत्व

औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कच्चे माल जैसे कपास, लकड़ी, गन्ना, जूट, तिलहन, आदि को विनिर्माण उद्योगों को प्रदान करता है। रोजगार और आजीविका निर्माण में उच्च हिस्सेदारी के कारण कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र अनाज और खाद्यान्न, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खनन और पशुपालन प्रदान करते हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता और इसके कारण

ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की मूल समस्या है। किसानों को उत्पादक और अनुत्पादक दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। अनुत्पादक ऋण ग्रामीण क्षेत्र के कुल ऋण के आधे से अधिक होते हैं। ये ऋण उत्पादन या उत्पादकता वृद्धि में योगदान नहीं करते हैं। ये ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र से अत्यधिक ब्याज दर पर लिए जाते हैं। ये ऋण मुख्य रूप से ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कारण हैं, जो न केवल आकार में बढ़ रहे हैं, बल्कि एक दुष्चक्र भी है।
गरीबी ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण है। भूमि पर भारी दबाव के कारण, औसत भारतीय किसान की आय बहुत कम है। सीमांत किसान को अपने जीवन यापन के खर्च के लिए धनराशि उधार लेनी पड़ती है। पैतृक ऋण भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक और महत्वपूर्ण कारण है। किसान अपने पुश्तैनी कर्ज को चुकाना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। भूमि के उप-विभाजन और विखंडन के कारण छोटी जोत, कृषि-उत्पादकता कम रहती है, जिसके परिणामस्वरूप कम कृषि आय होती है। यह किसानों की ऋणग्रस्तता को और बढ़ाती है। भारत में, 66 प्रतिशत खेती योग्य क्षेत्र वर्षा आधारित है और अधिकांश किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। बारिश में अनिश्चितता आय की अनिश्चितता में भी परिलक्षित होती है जिससे ऋण की लगातार और नियमित आवश्यकता होती है।

अधिकांश भारतीय किसान अनपढ़ हैं। उन्हें गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए उधार देने के लिए सूदख़ोर और बिचौलिए द्वारा गुमराह किया जाता है, जिसका पुनर्भुगतान बेहद मुश्किल हो जाता है। किसान जन्म, विवाह और मृत्यु के समय अनुष्ठानों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, जो वे अनौपचारिक क्षेत्र से ब्याज की उच्च दरों पर उधार लेते हैं। औपचारिक बाजार या मंडियों की कमी के कारण, भारत में छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर अपनी उपज को बाजार से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके ऋण और बढते हैं। इस प्रकार, वे ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं।

ग्रामीण ऋण, ग्रामीण ऋण के प्रकार और स्रोत

जैसा कि हमने देखा है, किसानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, अर्थात्, अतिरिक्त भूमि, औजार और उपकरण, उर्वरक और बीज खरीदने के लिए। उन्हें पुराने कर्ज चुकाने, शादी, मृत्यु, धार्मिक समारोहों जैसे व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, फसल की बुवाई और कृषि उपज की बिक्री के बाद आय की प्राप्ति के बीच की अवधि लंबी होने के कारण, उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश कृषक परिवार छोटे और सीमांत भूमि धारक हैं, जो बस जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त उत्पादन करते हैं और उनके पास कोई बचत नहीं होती जो वे निवेश के लिए उपयोग कर सकें।

समय अवधि के आधार पर, किसानों की ऋण आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्थायी रूप से संपत्ति या पूंजीगत वस्तुओं जैसे भूमि, उपकरण, ट्रैक्टर, नलकूप आदि प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। ये ऋण 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। मध्यम ऋण मुख्य रूप से कुओं की खुदाई, मशीनरी खरीदने, बाड़ का निर्माण आदि के लिए, एक से पांच साल की अवधि के लिए होता है। बीज, उपकरण, खाद और उर्वरक खरीदने के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। यह ऋण 6 से 12 महीने की अवधि के लिए सहकारी समितियों,सूदख़ोरों और बैंकों द्वारा जरूरतमंद ऋणी को दिया जाता है। किसानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

a) उत्पादक ऋण वह ऋण है, जिसकी आवश्यकता किसानों को आर्थिक गतिविधियों जैसे कि खाद, बीज, ट्रैक्टर, भूमि आदि की खरीद के लिए होती है। इस प्रकार के ऋण की कोई

निश्चित अवधि नहीं होती है। एक किसान बीज खरीदने के लिए अल्पावधि ऋण ; उर्वरक आदि और भूमि, भारी मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए दीर्घकालिक ऋण ले सकता है।

b) अनुत्पादक ऋण वह ऋण है, जिसकी आवश्यकता किसानों को अपनी सामाजिक, धार्मिक और अन्य गैर-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। इसे अनुत्पादक और उपभोग ऋण के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर अनुत्पादक ऋण को लघु अवधि या मध्यम अवधि के लिए दिया जाता है।

ग्रामीण ऋण के स्रोतों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,

(i) गैर-संस्थागत स्रोत या अनौपचारिक क्षेत्र और

(ii) संस्थागत स्रोत या औपचारिक क्षेत्र।

गैर-संस्थागत स्रोत या अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी और दलाल, जमींदार, संबंधी और मित्र शामिल होते हैं। उनके द्वारा प्रदान किया गया ऋण 1951-52 में कुल वित्तीय आवश्यकता का लगभग 93.6 प्रतिशत था, जो वर्तमान में घटकर 30 प्रतिशत हो गया है। साहूकारों का कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि वे उच्च ब्याज दर लेते हैं और खातों में हेरफेर करने के लिए जाने जाते हैं। ब्याज और / या ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, वे किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा, वे मजदूरी का भुगतान किए बिना काम करवा कर श्रमिकों का शोषण करते हैं। स्वतंत्रता के समय साहूकार ग्रामीण ऋण के प्रमुख स्रोत थे। बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों के विकास के साथ जो प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, साहूकार अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं हैं।

संस्थागत स्रोत या औपचारिक क्षेत्र

ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना में आज कई संस्थाएं, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंकों का एक समूह शामिल है। उनसे सस्ती दरों पर पर्याप्त ऋण देने की उम्मीद की जाती है। हाल ही में, स्व-सहायता समूह (SHG) औपचारिक-ऋण प्रणाली में खाई को भरने के लिए उभरे हैं।

सहकारी साख समितियां कृषि ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो किसानों की कुल ऋण आवश्यकताओं का लगभग 40 प्रतिशत है। (i) अल्पकालिक ऋण और (ii) दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी ऋण संरचना के दो पक्ष हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। वे ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं और किसानों के साथ उनकी अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे संपर्क बनाए रखती हैं। वित्त की अपनी आवश्यकताओं के लिए, यह एक केंद्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध होती है जो राज्य और जिला स्तर पर संचालित होता है। वर्तमान में, ऐसे 350 से अधिक बैंक हैं। दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भूमि बंधक बैंकों और कृषि विकास बैंकों को बढ़ावा दिया गया है। ऋण मुख्य रूप से ट्रैक्टर और ट्यूबवेल की खरीद के लिए होते हैं।

सहकारी क्षेत्र का कार्य किसानों को ऋण का समय पर और नियमित प्रवाह प्रदान करना है; वे ग्रामीण क्षेत्रों से साहूकारों को कम करते हैं और धीरे-धीरे खत्म करते हैं। इसके अलावा वे देश के सभी क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं, वे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रमों का वित्तपोषण सहकारी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

सहकारी क्षेत्र की कमजोरियाँ

सहकारी क्षेत्र आर्थिक और प्रशासनिक रूप से कमजोर बना हुआ है और फलस्वरूप किसानों को आवश्यक ऋण नहीं दे पा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) पास संचालन का छोटा क्षेत्र है और इस प्रकार कम सदस्यता है। कम व्यवसाय के कारण, उनकी आय बहुत कम है और इसलिए वे ठीक से नहीं चल सकते हैं। उनकी वृद्धि में गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन देखा गया। कुल ऋण में से 70 प्रतिशत केवल आठ राज्यों में है। ऋण की वसूली में मुख्य कमियां निहित हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋण अतिदेय लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, वे संगठनात्मक और प्रबंधकीय अक्षमता से पीड़ित हैं।

वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंक सभी कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अग्रिम ऋणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। छोटी, मध्यम या

लंबी अवधि के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम ऋण हो सकता है। अल्पावधि फसल ऋण या उत्पादन ऋण का रूप ले सकता है। इन ऋणों को फसलों की कटाई के बाद एक महीने या दो महीने की अवधि के भीतर चुकाना पड़ता है। मध्यम और दीर्घकालिक ऋण विकास कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं जो पूंजी प्रधान होते हैं। अधिकतम वापसी अवधि 15 वर्ष है। अप्रत्यक्ष अग्रिमों में उर्वरक-विक्रेताओं को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया ऋण शामिल है। उनमें सहकारी दुग्ध समितियों, भेड़ प्रजनकों, सहकारी समितियों को दिए गए अग्रिम ऋण भी शामिल होते हैं, जो बदले में दूध, पशु, भेड़, आदि की खरीद के लिए अपने सदस्यों को ऋण सहायता प्रदान करते हैं।

ग्रामीण कृषि शाखाओं के संचालन की लागत बहुत अधिक है और ग्रामीण शाखाओं को खोलने और संचालन में भारी नुकसान होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए अनिच्छुक होते हैं और कृषि क्षेत्र में कम पहल और रुचि रखते हैं। संचार और परिवहन प्रणाली की कमी के कारण बैंकों के केंद्रीय कार्यालय सुदूर ग्रामीण शाखाओं से कटे हुए हैं। परिणामस्वरूप, विश्वसनीय आंकडो की कमी के कारण अंतर-शाखा बैंक समायोजन संभव नहीं हो पाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किए गए हैं। नाबार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण और संबंधित सुविधाएं प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरबी के लगभग 90 प्रतिशत ऋण कमजोर वर्ग को प्रदान किए जाते हैं। वे ब्याज की कम दर पर ऋण प्रदान करते हैं और जमा पर ब्याज की उच्च दर देते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) के कार्य

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को सस्ते दर पर ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं। यह छोटे और सीमांत किसानों को खेतों के लिए भूमि और आवश्यक इनपुट खरीदने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से बाहर निकालना है। यह उन्हें अपनी आय क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से खेती करने का अधिकार देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ऋण का उपयोग केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाए।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण लोगों के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जहां वाणिज्यिक बैंक और अन्य संस्थान सेवा नहीं देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों के बीच बचत को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अधिक उत्पादक गतिविधियों में शामिल करते हैं। वे ग्रामीण लोगों को अनुत्पादक ऋण लेने के लिए भी हतोत्साहित करते हैं।

(iii) आरआरबी गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित कार्य भी करते हैं। ग्रामीण भारत में बहुत से कारीगर हैं, जिनके पास विशिष्ट तरीके से हस्तशिल्प बनाने का कौशल है। उनके पास उद्यमी प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पहल करने में असमर्थ हैं। जब वे गरीबी में रहते हैं, तो वे अक्सर अपने उत्पादों को बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्हें सस्ते और आसान ऋण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने माल के उत्पादन के लिए कच्चा माल और अन्य आवश्यक सामग्री खरीद सकें और इसलिए अपने माल की गुणवत्ता में सुधार करें। बेहतर गुणवत्ता वाले सामानों की बिक्री उन्हें आय प्रदान करेगी और इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

(iv) गाँवों, उप-शहरी क्षेत्रों और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में छोटे उद्यमी हैं जो खुदरा व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगे हुए हैं। व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। आरआरबी उन्हें बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं ताकि वे अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक कच्चा माल और अन्य पूंजी खरीद सकें। आरआरबी स्वयं-नियोजित व्यक्तियों को ऋण देते हैं जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD)

नाबार्ड की स्थापना जुलाई, 1982 में की गई थी। इसकी रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी है। 500 करोड़ रु। आरबीआई ने शेयर पूंजी का आधा योगदान दिया था जबकि अन्य आधा हिस्सा भारत

सरकार द्वारा दिया गया था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। यह आरबीआई द्वारा अनुमोदित राज्य सहकारी बैंकों, आरआरबी, भूमि विकास बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नाबार्ड लघु उद्योग, ग्रामोद्योग और ग्रामीण शिल्प के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की गतिविधियों का भी समन्वय करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने और काश्तकारों और छोटे किसानों को उनके भूनिर्माण को समेकित करने में भी मदद करता है।

स्वयं सहायता समूह (SHG) और माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम

ग्रामीण ऋण के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम एक उभरती हुई घटना है। एसएचजी ग्रामीण परिवारों के बीच बचत को बढ़ावा देते हैं। छोटी बचत को स्वयं सहायता समूह द्वारा जुटाया जाता है और अपने विभिन्न सदस्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर के ऋण रूप में पेश किया जाता है। बिना किसी सुरक्षा और कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की जाती है। वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में सात लाख से अधिक एसएचजी संचालित हैं। एसएचजी द्वारा ऋण प्रावधान को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। ये कार्यक्रम छोटे उधारकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि ये अनौपचारिक ऋण वितरण तंत्र 'के रूप में काम करते हैं जिनमें कोई औपचारिकता नहीं होती है।

ग्रामीण बैंकिंग - एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन

1969 के बाद से, जब वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ग्रामीण बैंकिंग ने बड़ा विकास किया है। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण विस्तार ने किसानों को सेवाएं और ऋण सुविधाएं प्रदान करके कृषि और गैर-कृषि उत्पादन बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। वे बेहतर पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार साहूकारों को समाप्त करने में मदद करते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं की सुविधा के लिए भी ऋण देते हैं।

ग्रामीण बैंकिंग की सीमाएं

सहकारी क्षेत्र, आरआरबी और वाणिज्यिक बैंक सभी किसानों की ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं के साथ सामना करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, कुछ गंभीर सीमाएँ हैं जिनके कारण ग्रामीण ऋण अभी भी चिंता का विषय है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं।

i. बैंकिंग ऋण या संस्थागत ऋण को संपार्श्विक (Collateral) के साथ जोड़ा गया है, और सीमांत किसानों के पास संपार्श्विक की पेशकश करने की क्षमता कम है, इस कारण छोटे और सीमांत किसान इसके प्रमुख लाभार्थी नहीं हैं।

ii. सरकार अक्सर किसानों से ऋण की वसूली पर बहुत ढीली रही है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में अतिदेय किस्तें दी गई हैं। लगभग ४०-४२ प्रतिशत ऋण चुकता नहीं किये गये हैं।

iii. आवश्यकता की तुलना में ऋण की उपलब्धता अपर्याप्त है। हालांकि समय के साथ ऋण के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी यह मांग से कम है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण किसानों को भारी मशीनरी की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

iv. व्यावसायिक बैंकों के अलावा, अधिकांश वित्तीय संस्थान किसान परिवारों के बीच बचत की संस्कृति विकसित करने में विफल रहे हैं। सीमांत किसानों की आय का स्तर कम होता है और वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। इससे अंततः कम बचत होती है।

v. धार्मिक रीति-रिवाजों और पारिवारिक कार्यों पर अत्यधिक व्यय ग्रामीण क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा है। यह ग्रामीण ऋण में लगी विभिन्न संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य को विफल करता है।

भारत में कृषि ऋण की समस्या को सुधारने के सुझाव

कृषि ऋणों की वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। आसान नियम और शर्तों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधा दी जानी चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए और उनका कार्य पारदर्शी और कुशल होना चाहिए। उन्हें उधारकर्ताओं के साथ संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें बहु-उद्देश्यीय समाजों में परिवर्तित किया

जाना चाहिए। आरबीआई को दीर्घकालिक ऋण के लिए अधिक धन जारी करने में सक्षम होना चाहिए। किसानों के बीच अधिक बचत को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों को नई योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। भंडारण सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसान अपनी उपज का भंडार कर सकें और इसे ऋण के लिए जमानत के रूप में गिरवी रख सकें। ऋण संस्थाओं को दिए गए ऋण के उपयोग पर नजर रखनी चाहिए। इसके लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसानों को मौजूदा ऋणों के सभी विवरणों को दिखाते हुए आधार से जुड़ी पासबुक दी जानी चाहिए। यह एक ही धरोहर के आधार पर लिए गए विभिन्न ऋणों की जांच रखेगी। पासबुक में उनकी जमीन और अचल संपत्तियों का विवरण भी होना चाहिए। इससे ऋण देने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी।

सारांश

बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार से ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरित क्रांति के बाद इसने किसानों को अपनी उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं और ऋण सुविधाओं और विभिन्न प्रकार के ऋणों का लाभ उठाने में मदद की। अकाल अतीत की घटनाएं बन गए; हमने अब खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है जो अनाज के प्रचुर बफर स्टॉक में परिलक्षित होती है। हालांकि, यह सब हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ सब ठीक नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों के संभावित अपवाद के साथ, अन्य औपचारिक संस्थान जमा राशि जुटाने और सार्थक उधारकर्ताओं और प्रभावी ऋण वसूली के लिए संस्कृति विकसित करने में विफल रहे हैं। कृषि ऋण की डिफ़ॉल्ट दरें बहुत अधिक हैं।

इस प्रकार, ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार और प्रचार ने सुधारों के बाद एक वापसी की है। स्थिति में सुधार करने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को उधारदाताओं के साथ संबंध बनाने के लिए सिर्फ उधारदाताओं से अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। मितव्ययिता और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग की आदत को किसानों के बीच भी बढ़ाने की जरूरत है।